

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 28/2017

बउनवान

रमेशचन्द्र पुत्र श्री भँवरलाल आयु 42 वर्ष जाति-कुम्हार निवासी-जालेडा
तहसील-बारां, जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)



दिनांक- 24.01.2019

1- अपीलांट ने जयें तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 05.10.2016 से राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय ने उसे ग्राम 0.16 हैक्टर किस्म चामर मानकर बेदखली, 30 सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध विपरीत होने से निरस्त किया जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाब दे ही अनुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलांट को हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर जायाव किया है। अपीलांट उक्त आराजी पर कोई कब्जा काशत नहीं है तथा तब भी जवाब दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील उचित शुल्क व जानकारी से अवधि मध्य पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2- इस पर प्रकरण रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की

प्रोपर तामील नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जाँच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 693/14 निर्णय दिनांक 28.11.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपात् अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते हैं।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलद्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1326/15 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जावे कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां को दो माह में उपस्थित होकर अप्पडरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से इन्तुहा नहीं जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 05.10.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को सरे इजलास लिखिया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राब०)